petition in the High Court of Delhi. The Court has since delivered the judgement which is being studies. Decision in this case is expected to be taken shortly.

Installation of Telephone connections sanctioned during the Janta Regime

2545. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the fate of the telephone connections sanctioned by the Minister of Communications during the Janata regime;

(b) whether it is a fact that installation of these telephones has already been much delayed; and

(c) if so, what is the time schedule fixed for installation of these sanctioned telephones?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) As some fake sanctioned orders for out of turn telephone connections were noticed, an investigation was entrusted to the CBI and pending investigation, all the pending sanction orders as on 28-6-91 in the country were ordered to be held in abeyance.

(c) All the genuine saction orders would be given effect to after the CBI submits its report in this matter to the Department.

गुजरात में डाक सुविधायों में हुई प्रगति

2546. श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछले वर्ष के दौरान किए गए उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके परिणामस्वरूप डाक सुविधाओं में वृद्धि हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय गुजरात में 8933 डाकघर सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं योजना स्कीम के अंतर्गत उत्तरोत्तर नए डाकघर खोलकर डाक-सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । 1992–93 के दौरान गुजरात में 30 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 5 विभागीय उप डाकघर खोले गए हैं ।

Telephone Services in Bombay and Delhi

2547. SRHI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lakhs of telephones in Bombay and Delhi have been lying out of order following heavy rains here;

(b) if so, what is the day-wise number of complaints registered in Bombay and Delhi from 1st June, 1993, till date;

(c) what is the number of telephones made functional each day together with the number of telephones lying out of order;

(d) whether Government are considering to introduce cable less telephone system in the country specially in Bombay and Delhi;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

TEH MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e) Tenders were invited from the Indian companies with a view to provide Cellular Mobile Telephone Service, which is cableless telephone system, initially in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras on a licence basis. 8 bidders, two in each city, were provisionally selected. Some of the unsuccessful bidders filed a civil writ petition in the High Court of Delhi. The judgement in the case has since been delivered and is under study.

(f) *Does not arise.*

बंगलौर में तार-रहित टेलीफोन प्रणाली

2548. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** की : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बंगलौर में तार-रहित टेलीफोन प्रणाली की शुरुआत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस तरह की प्रणाली देश के अन्य नगरों में भी प्रारम्भ करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही उठता ।

(ग) और (घ) आरंभ में बंबई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास में लाइसेंस आधार पर सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा, जो केबल रहित टेलीफोन प्रणाली हैं, प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय कंपनियों से निविदायें मांगी गई थी । 8 बोलीदाताओं को, अर्थात प्रत्येक शहर से दो-दो को अंतिम रूप से चुना गया था । कुछ असफल बोलीदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की है । इस मामले में फैसला सुना दिया गया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है । आठवीं योजना के दौरान बंगलौर सहित देश के अन्य बड़े शहरों में भी सेल्यूलर सचल प्रणाली प्रदान करने की योजना है ।

उपभोक्ता टेलीफोनों पर फैक्स प्रणाली के लगाए जाने के लिए शुल्क

2549. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं को अपने-अपने टेलीफोनों पर फैक्स प्रणाली लगाने के लिए 3000/- रुपये के वार्षिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस पर प्रभारित सालाना शुल्क के कारण फैक्स के उपभोक्ताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ टेलीफोन उपभोक्ता अपने टेलीफोनों पर अवैध रूप से फैक्स प्रणाली लगाए हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार टेलीफोन राजस्व में वृद्धि करने के लिए फैक्स सुविधा निःशुल्क देने का विचार रखती है ;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । फैक्स उपकरण वाले उपभोक्ताओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है ।